THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The land in Delhi is acquired by the Delhi Administration under the Land Acquisition Act and not by the D.D.A. The lands acquired for planned development of Delhi are placed at the disposal of the D.D.A. The cases for acquisition of 11,462.36 acres of land for planned development of Delhi are being processed by Delhi Administration at present.

The land is required for a public purpose, namely, planned development of Delhi.

The compensation is being paid by the Delhi Administration as per the amended provisions of Land Acquisition Act, determined on the basis of Sale deeds registered by the Sub-Registrars in respect of the land in the surrounding villages, the rates fixed by the various courts and also on the basis of market value prevalent on the date of notification under section 4. In addition to the compensation the farmers, whose lands are acquired are given the following rehabilitation benefits:—

(i) Alternative residential plots on the scales laid down by the Lt. Governor of Delhi are allotted to them.

(ii) 15 per cent of the shops constructed by the D.D.A. are allotted to bonafide farmers whose lands are acquired or who are rendered jobless consequent on acquisition of land.

गोरखपुर में स्थित भारतीय उर्वरक निगम का एकक

813. **श्री शरद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने उच्च अधिकारी एवं इंजीनियर हैं जो गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम के एकक में इसके प्रारंभ से ही लगातार कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन उच्चाधिकारियों ने कुछ समय पहले विदेशों से करोड़ों रुपये की मशीनें मंगवाई थीं जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इन्हीं कारणों से कारखाना भारी घाटे में चल रहा है ; यदि हां, तो पिछले 10 वर्षों के दौरान आयात की गई ऐसी मशीनों की कीमत क्या है जिनका प्रयोग नहीं किया गया ;

(ग) क्या उन उच्चाधिकारियों को, जिनका कार्यकाल 3 या 5 साल से अधिक है, स्थानांतरित करके कार्यकुशलता को सुधारने तथा एकक का उत्पादन बढ़ाने का सरकार ने कोई विचार किया है ; और

(घ) इस संबंध में क्या अन्य दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) उप मुख्य अभियन्ता या उसके ऊपर के ओहदे के 12 अधिकारी, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (एफसी आई) के गोरखपुर एकक में प्रारंभ से लगातार कार्य कर रहे हैं ।

(ख) गत 10 वर्षों के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपये की मशीनरी गोरखपुर एकक के लिये आयात की गयी थी । इस का पूर्ण इस्तेमाल किया गया है ।

(ग) यद्यपि निगम के अन्दर ही अन्तः एकक स्थानान्तरण समय-समय पर होते रहते हैं, गोरखपुर एकक में 3 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाले अधिकारियों को स्थानान्तरित करने का इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) पुराने उपस्कर को 9.46 करोड़ रुपये की लागत पर प्रतिस्थापित करने के लिये विभिन्न अल्पावधिक उपचारी उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं । निगम ने 39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर यूरिया संयंत्र को प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत करने तथा वर्तमान अमोनिया संयंत्र की समस्याओं के समाधान का भी प्रस्ताव किया है ।